(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना वेतन दिया जा रहा है और ये वेतन कब से दिया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिये जा रहे वेतन पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव रखती है; यदि हां, तो कब तक।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का (अतिरिक्त प्रभार) (कु. ममता बैनर्जी) :(क) और(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाए स्थानीय समुदाय से चुनी हुई अवैतनिक और अंशकालिक स्वैच्छक कार्यकर्ता होतीं हैं। अतः वे न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कवर नहीं होतीं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए निर्धारित मानदेय (1 जुलाई, 1986 से लागू) निम्नानुसार हैं :

(ii) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	रु० प्रतिमाह
मैट्रिकुलेट	275.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो	300.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो	325.00
नान-मैट्रिक	225.00
नान-मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो	250.00
नान-मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो	275.00
(ii) सहायिका	110.00

(ग) जी, हां। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में संशोधन करने का मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

इन्दौर के निकट शुष्क बन्दरगाह की स्थापना

1245. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर के निकट एक शुष्क-बन्दरगाह स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में सरकार को एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पहले ही भेजा जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शुष्क बन्दरगाह कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देगी; और

(ग) शुष्क-बन्दरगाह से कुल कितने निर्यात होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी. चिदम्बरम्) (क) से (ग) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिम० ने मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर राज्य में शुष्क बन्दरगाहों की स्थापना के बारे में एक व्यवहार्यता अध्ययन किया है। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि चारों क्षेत्रों में से निर्यात/

आयात कन्टेनर हैन्डलिंग की सर्वाधिक अनुमानित क्षमता इन्दौर क्षत्र की (4850 टी ई यू–(टवन्टी फुट इक्विवलेन्ट यूनिटस) अनुमानित है जिसमें लदे हुए निर्यात के लगभग 2,600 टी ई यू शामिल है। राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। कन्टेनर कारपोरेशन आफ इन्डिया और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन्दौर क्षत्र के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण कर रह हैं। किन्तु, शुष्क बन्दरगाह की स्थापना भूमि तथा निधियों की उपलब्धता और परियोजना की पारस्परिक अग्रता पर निर्भर करेगी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या

1246. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित पड़ हैं; और

(ख) क्या न्यायाधीशों के पद लम्बी अवधि से रिक्त पड़ होने के कारण लम्बित मामलों की संख्या बढ़ रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम्) : (क) 31 मार्च, 1991 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 50974 मामले (मुख्य मामले) लम्बित थे।

(ख) लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि के कई जटिल कारण हैं जिनके अंतर्गत अधिक मामलों का संस्थित किया जाना और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े रहना है।

Financing of Ajanta and Ellora project by Japan

1247. SHRI VISHWASRAO RAM.. RAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Japanese Government is ready to finance the Ajanta and Ellora project; and

(b) if so, by when a final decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Tourist Development Plan of Ajanta and Ellora Region at a total cost of Rs. 195 crores is one of the projects posed for assistance from OECF of Japan jn the 1991-92 loan package.

(b) A final decision is expected during the financial year 1991-92.

Meeting between Industrialists of USA and India

1248. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether some delegation of prominent industrialists of U.S.A. have met Indian industrialists in March, 1991 to augment existing commercial ties between the two countries;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the meeting had positive results; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A Round Table Conference was organised on 12th March, 1991 at New Delhi under the aegis of the Indo-US Joint Business Council.